भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1939
दिनांक 31 जुलाई 2025

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में जैव-ईंधन का उत्पादन

†1939 **श्री कामाख्या प्रसाद तासा:**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में जैव-ईंधन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की जैव-ईंधन परियोजना में कुल कितनी धनराशि निवेश की गई है;
(ग) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी का क्या नाम है;
(घ) उक्त परियोजना किस तिथि को शुरू की गई थी और उसका उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है;
(ङ) उक्त परियोजना की वर्तमान लागत सहित कुल लागत कितनी है; और
(च) उक्त परियोजना के अंतर्गत संभावित रोजगार सृजन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सरकार राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति के अंतर्गत, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत विभिन्न उद्देश्यों के साथ पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता, कच्चे तेल पर आयात निर्भरता में कमी, विदेशी विनिमय की बचत तथा घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने देश भर में कृषि अवशेषों सहित विभिन्न अपशिष्ट/जैव-मास स्रोतों से संपीड़ित जैवगैस (सीबीजी) के उत्पादन और उपयोग के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से सतत (किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प) पहल शुरू की है। इस पहल के तहत तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा फीड स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर देश भर में सीबीजी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

सरकार द्वारा वर्ष 2014 से देश भर में जैव-ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का विस्तार, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत गन्ना आधारित एथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए प्रशासनिक मूल्य व्यवस्था, ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल पर घटी हुई 5% जीएसटी दर, खाद्यानों के साथ-साथ शीरा से एथेनॉल उत्पादन हेतु एथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाएं (ईआईएसएस), एथेनॉल उत्पादन हेतु सहकारी चीनी मिलों के लिए मौजूदा गन्ना आधारित डिस्टिलरी को बहु-फीडस्टॉक संयंत्रों में परिवर्तित करने के लिए एक समर्पित अनुदान योजना, समर्पित एथेनॉल संयंत्रों (डीईपीज) के साथ तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा दीर्घकालिक ऑफटेक करार(एलटीओएज) आदि शामिल हैं।

सरकार ने "प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकुल फसल अवशेष निवारण) योजना" को भी लिग्नोसेल्युलोसिक जैवमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके देश में उन्नत जैव ईंधन परियोजनओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया है।

(ख) से (च): नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जो असम जैव-एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड (एबीईपीएल) के माध्यम से असम राज्य में 2जी बांस आधारित जैव-रिफाइनरी परियोजना स्थापित कर रही है। इस परियोजना को जून, 2020 में 1750 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी प्रदान की गई थी तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। परियोजना की संशोधित लागत 4930 करोड़ रुपये है, जिसके सापेक्ष अब तक 4200 करोड़ रुपय का व्यय किया जा चुका है। परियोजना यांत्रिक रूप से पूरी हो चुकी है और वर्तमान में कमीशनिंग के उन्नत चरण में है। इस परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित कुल रोजगार संख्या निम्नानुसार है:

विवरण	**प्रत्यक्ष रोजगार (संख्या)**	**अप्रत्यक्ष रोजगार (संख्या)**	**कुल**
निर्माणाधीन चरण	30	2000	2030
प्रचालन चरण	150	50000	50150

*****